SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

IBDF URGES TRAI TO PAUSE 12-MINUTE AD

The Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF) has requested the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to defer enforcement of the 12-minute-per-hour television advertising cap, citing that the matter is sub judice. The final arguments in the case are scheduled before the Supreme Court on January 27.

Sources said news broadcasters have supported IBDF's stance in their individual responses to TRAI. However, the regulator has emphasized that broadcasters must comply with the current rules until a court issues a formal order. TRAI, following a meeting with broadcasters after issuing show-cause notices in November for alleged violations, reiterated that the pending judicial review does not suspend the applicability of the regulation.

The long-dormant 12-minute cap, frozen for over a decade, has resurfaced with TRAI issuing more than 250 notices to enforce compliance. Broadcasters warn that implementing the cap now could disrupt linear TV economics, already under pressure from declining ad revenues, rising content costs, and a migration of audiences to digital and free-to-air platforms. Industry leaders have called for a measured approach, noting that exceeding the cap in some hours does not indicate uniform violation across all programming.

TV9 NETWORK DISMISSES PROMOTER EXIT SPECULATION

TV9 Network has firmly denied reports claiming its promoters are planning an exit from the media group.

In an official statement, the network said, "TV9 Network remains fully committed to its vision and ongoing operations. The information being circulated should not be considered accurate." The statement

आईबीडीएफ ने ट्राई से 12 मिनट के विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह किया

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से प्रति घंटे 12 मिनट के टेलीविजन विज्ञापन की सीमा को लागू करने में देरी करने का अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि मामला अभी कोर्ट में है। इस मामले में अंतिम बहस 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।

सूत्रों ने बताया कि न्यूज प्रसारकों ने ट्राई को दिये गये अपने अलग-अलग जवाबों में आईबीडीएफ के रूख का समर्थन किया है। हालांकि, रेगुलेटर ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक कोर्ट कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं करता,तब तक प्रसारकों को मौजूदा नियमों क पालन करना होगा। नवंबर में कथित उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद प्रसारकों के साथ एक मीटिंग के बाद ट्राई ने दोहराया कि लंबित न्यायिक समीक्षा रेगुलेशन की लागू होने की स्थिति को निलंबित नहीं करती है।

लंबे समय से बंद 12 मिनट की लिमिट, जो एक दशक से ज्यादा समय से रूकी हुई थी, अब ट्राई द्वारा नियमों का पालन करवाने के लिए 250 से ज्यादा नोटिस जारी करने के बाद सामने आयी है। प्रसारक चेतावनी दे रहे हैं कि अब इस लिमिट को लागू करने से लीनियर टीवी की इकोनॉमी खराब हो सकती है, जो पहले से ही विज्ञापन से होने वाली कमी, कंटेंट की बढ़ती लागत, और दर्शकों के डिजिटल और फ्री-टू-एयर प्लटफॉर्म में जाने से दबाव में है। उद्योग ने सोच समझकर कदम उठाने की बात कही है, यह देखते हुए कि कुछ घंटों में लिमिट पार करने का मतलब यह नहीं है कि सभी कार्यक्रम में एक जैसा उल्लंघन हुआ है।

टीवी 9 नेटवर्क ने प्रमोटरों के बाहर निकलने के अटकलों को खारिज किया

टीवी 9 नेटवर्क ने उन रिर्पोटों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रमोटर मीडिया गुप से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं।

एक आधिकारिक बयान में, नेटवर्क ने कहा कि 'टीवी9 नेटवर्क अपने विजन और चल रहे संचालन के लिए पूरी तारह प्रतिबद्ध है। जो जानकारी फैलाई जा रही है उसे सही नहीं माना जाना चहिए।'

clarified that there has been no change in promoter involvement or strategic direction.

TATA PLAY VS CULVER MAX: TDSAT SETS FINAL HEARING

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) has extended interim relief for Tata Play, maintaining the stay on the ?128.42 crore demand raised by Culver Max (Sony Pictures). The tribunal has scheduled the final hearing for February 2026.

The dispute began in May 2025, when Tata Play removed 25 Sony channels from its DTH packs citing contractual issues. Culver Max alleged this violated interconnection agreements and TRAI regulations. Earlier, TDSAT restricted the broadcaster from displaying static images or scrolls against Tata Play, while allowing limited clarifications on social media.

MIB CANCELS 1,117 MSO REGISTRATIONS

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has cancelled registrations of 1,117 Multi-System Operators (MSOs), reducing the number of active MSOs to 787. Reasons include non-compliance, late submissions, failure to secure security clearance, and incomplete documentation. Industry experts believe this move will enhance regulatory compliance and improve service quality, sending a strong message about adherence to regulatory frameworks.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
सत्यमेव जयते

JIOSTAR REAFFIRMS ICC MEDIA RIGHTS PARTNERSHIP IN INDIA

JioStar and the International Cricket Council (ICC) have dismissed speculation about JioStar exiting their media rights agreement. Both organisations confirmed the 2024-2027 contract remains fully in force, with JioStar continuing as the ICC's official media rights partner in India.■

बयान में यह साफ किया गया है कि प्रमोटरों की भागेदारी या स्ट्रेटेजिक दिशा में किया बदलाव नहीं हुआ है।

टाटाप्ले बनाम कल्वर मैक्स

टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसेट) ने टाटा प्ले को अंतरिम राहत दी है, और कल्वर मैक्स (सोनी पिक्चर्स) द्वारा मांगे गये **128.42** करोड़ रुपये पर रोक बरकरार रखी है। ट्रिब्यूनल ने अंतिम सुनवाई फरवरी **2026** के लिए तय की है।

यह विवाद मई **2025** में शुरू हुआ, जब टाटा प्ले ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए अपने डीटीएच पैक से **25** सोनी चैनल को हटा दिये। कल्वर मैक्स ने आरोप लगाया कि इससे इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ट्राई के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले टीडीसेट ने प्रसारक को टाटा प्ले के खिलाफ स्टैटिक इमेज या स्क्रॉल दिखाने से रोक दिया था, जबकि सोशल मीडिया पर सीमित स्पष्टीकरण की अनुमति दी थी।

एमआईबी ने 1117 एमएसओ के लाइसेंस रद्द किये

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने **1117** मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिये हैं, जिससे एक्टिव एमएसओ की संख्या घटकर **787** रह गयी है। इसके कारणों में नियमों का पालन न करना, देर से सबमिशन, सुरक्षा मंजूरी हासिल करने मं विफलता और अधूरे दस्तावेज शामिल हैं। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रेगुलेटरी नियमों का पालन बेहतर होगा और सेवा की क्वालिटी में सुधार होगा, जिससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने के बारे में एक कड़ा संदेश जायेगा।

जियोस्टार ने भारत में आईसीसी मीडिया अधिकार पार्टनरशिप की फिर से पुष्टि की

जियोस्टार और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मीडिया अधिकार अनुबंध से जियोस्टार के बाहर निकलने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दोनों संगठनों ने पुष्टि की है कि **2024-2027** का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से लागू है और जियोस्टार भारत में आईसीसी का आधिकारिक मीडिया अधिकार भागीदार बना रहेगा।■

BROADBAND & IPTV NEWS

ब्रॉडबैंड व आईपीटीवी न्यूज

PRASAR BHARATI'S WAVES OTT GETS BIG HITS

Prasar Bharati's OTT platform WAVES has recorded over 80 lakh downloads in its first year, the government informed the Lok Sabha. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan highlighted the platform's role in making Doordarshan and All India Radio archives, regional arts, classical music, literature-based programming, and multilingual content accessible globally.

WAVES OTT operates as a subscription-free public service platform, with advertising as its primary revenue source. It also provides a distribution framework for emerging filmmakers and creators, helping them reach diverse audiences worldwide. The platform is currently expanding its international footprint, developing revenue streams through strategic partnerships.

OTT CONTENT OUTSIDE CBFC, REGULATED BY IT RULES

The Centre clarified that content on OTT platforms remains outside the jurisdiction of the Central Board of Film Certification (CBFC) and is regulated under the IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

Under the rules, OTT platforms must follow a Code of Ethics, including age-based classification of content into five categories, and maintain mechanisms to address grievances. The regulatory framework establishes a three-tier system: self-regulation by publishers, oversight by self-regulatory bodies, and intervention by the Central Government if necessary.

बड़ी सफलता मिली प्रसार भारती के वेवस् ओटीटी को

सरकार ने लोक सभा को बताया कि प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेवस् ने अपने पहले साल में 80 लाख से ज्यादा डाउनलोड दर्ज किये हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरूगन ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव, क्षेत्रीय कला, शास्त्रीय संगीत, साहित्य आधारित कार्यक्रम और बहुभाषी कंटेंट को विश्वस्तर पर सुलभ बनाने में प्लेटफार्म की भूमिका पर प्रकाश डाला।

वेवस् ओटीटी एक सब्सक्रिप्शन मुक्त सार्वजनिक सेवा प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, जिसमें विज्ञापन इसका मुख्य राजस्व स्रोत है। यह उभरते हुए फिल्म निर्माताओं और क्रिएटर्स के लिए एक वितरण फ्रेमवर्क भी देता है जिससे उन्हें दुनिभर में अलग-अलग दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह प्लेटफॉर्म अभी अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर काम कर रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सहायता से राजस्व के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ओटीटी पर दिखाये जाने वाले कंटेंट सीबीएफसी के दायरे से बाहर, आईटी नियमों द्वारा रेगुलेटेड

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट किया जाता है।

नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होगा, जिसमें कंटेंट को उम्र के हिसाब से पांच श्रेणियों में बांटना और शिकायतों को दूर करने के लिए सिस्टम बनाये रखना शामिल है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तीन स्तरीय सिस्टम बनाया गया हैः प्रकाशक द्वारा स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा निगरानी और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार का दखल।

GOVERNMENT STRENGTHENS SAFEGUARDS FOR CHILDREN ONLINE

The IT Rules, 2021, and related provisions under the IT Act provide stringent measures to curb unlawful, obscene, or harmful content online. Platforms must implement parental controls and safeguards to protect minors from inappropriate material. ShareChat's QuickTV has introduced pin-based parental controls, age-specific content ratings, and structured access based on categories such as U, U/A 13+, U/A 16+, and A (Adult).

OTT'S SOUTH-FOCUSED GROWTH AND GLOBAL REACH

Industry experts note that South Indian content has become the growth engine for OTT platforms. Blockbusters like Pushpa, KGF, and Kantara, along with regional originals such as Suzhal: The Vortex, have created deep engagement and franchise loyalty. Platforms like Amazon Prime Video, Netflix, and JioHotstar are investing heavily in South-language originals, with JioHotstar earmarking Rs 4,000 crore for content and creator ecosystem development.

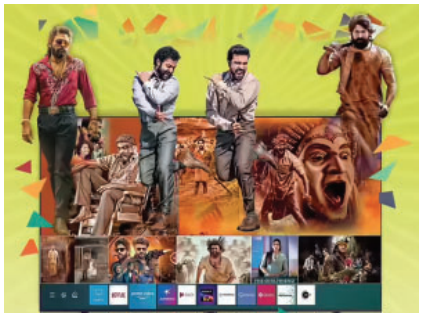

ACCESSIBILITY AND INCLUSIVE STREAMING

The Ministry of Information and Broadcasting has issued draft guidelines to make OTT content accessible for hearing- and visually-impaired users, proposing a two-phase implementation starting with public broadcasters like Prasar Bharati. The move aligns with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the UNCRPD.■

सरकार ने ऑनलाइन बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया

आईटी रूल्स 2021, और आईटी एक्ट के तहत संबंधित नियम ऑनलाइन गैर-कानूनी, अश्लील या नुकसानदायक कंटेंट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हैं। प्लेटफार्मों को नाबालिकों को गलत कंटेंट से बचाने के लिए पैरेंटल कंट्रोल और सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। शेयरचैट के क्विक टीवी टीवी पिन आधारित पेरेंटल कंट्रोल, उम्र के हिसाब से कंटेंट रेटिंग और यू, यू/ए 13+, यू/ए 16+, और ए (एडल्ट) जैसी श्रेणी के आधार पर स्ट्रक्चर्ड एक्सेस शुरू किया है।

ओटीटी की दक्षिण भारत केंद्रित विकास और वैश्विक पहुंच

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारतीय कार्यक्रम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए विकास इंजन बन गये हैं। पुष्पा, केजीएफ और कंतारा जैसे सुपरहीट के साथ-साथ सुजलः द वोर्टेक्स जैसे क्षेत्रीय मौलिक कार्यक्रमों ने जबरदस्त एंगेजमेंट और फ्रैंचाइजी लॉयल्टी बनायी है। अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिस्क और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स दक्षिणी भाषाओं के मूल कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रहे हैं जिसमें जियोहॉटस्टार ने कंटेंट और क्रिएटर इकोसिस्टम विकास के लिए 4000 करोड़ रु रखे हैं।

एक्सेसिबिलिटी और सबको साथ लेकर चलने वाली स्ट्रीमिंग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी कार्यक्रमों को सुनने और देखने में दिक्कत वाले इस्तेमालकर्ताओं के लिए आसान बनाने के लिए ड्रॉफ्ट दिशा निर्देश जारी की हैं। इसमें प्रसार भारती जैसे सार्वजनिक प्रसारक से शुरू करके इसे दो फेज में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार का यह कदम दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 और यूएनसीआरपीडी के मुताबिक है।■

CANAL+ SETTLES VAT DISPUTE

Canal+ has reached a settlement with French tax authorities over the VAT rate applied to its television subscription services, bringing an end to a long-running dispute that had weighed on the group as it accelerates its international pay-TV and streaming expansion.

In a regulatory filing, Canal+ said the agreement follows clarifications issued by tax authorities in September 2025, along with joint work to define and operationalise catch-up television services on its platform. The settlement confirms that a reduced VAT rate applies to Canal+'s TV subscription offerings.

The group has committed to a total payment of €363 million, with the payment schedule to be finalised at a later date. Canal+ said it does not expect future tax audits for subsequent years to result in material adjustments and confirmed that no further provisions will be made in its accounts related to the issue. The company had earlier indicated that an agreement in principle had been reached with authorities earlier in 2025.

ANGHAMI SHARES SURGE ON REVENUE INCREASE

Anghami's Nasdaq-listed shares jumped more than 40% in after-hours trading after the Middle East and North Africa (MENA) streaming group reported strong first-half results. Revenue for the six months to June 30, 2025 rose 97% year-on-year to $48.4 million (€41.2 million), driven largely by subscription growth following the OSN+ integration.

Subscription revenue climbed to $43.0 million (€36.6 million), while paid subscribers nearly doubled to 3.54 million. Registered users crossed 120 million. Anghami also highlighted a deepening relationship with Warner Bros. Discovery, following a $57 million (€48.5 million) strategic investment into OSN Streaming Ltd, Anghami's majority owner.

anghami

Despite the topline growth, Anghami posted a net loss of $37.1 million (€31.6 million), reflecting higher spending on OSN+ subscriber acquisition and integration. The company said cost optimisation efforts and scaling efficiencies are underway, supported by new partnerships with Noon, PlayStation and a distribution deal with Talabat.

SPORTDIGITAL EXTENDS SUPERCOPA DE ESPAÑA RIGHTS

German pay-TV broadcaster Sportdigital has renewed its exclusive Supercopa de España rights for Germany, Austria and Switzerland, extending the deal through the 2027/28 season.

sportdigital

The next tournament will be held in Saudi Arabia in January 2026, with semi-finals featuring FC Barcelona vs Athletic Bilbao and Real Madrid vs Atlético Madrid. All matches will air on Sportdigital Fußball and the Sportdigital+ app.

WARNER BROS. DISCOVERY TO RELAUNCH TLC

Warner Bros. Discovery (WBD) will relaunch TLC as a free-to-air entertainment channel in the UK and Ireland from January 2026, backed by a major slate of US scripted titles and UK originals.

TLC

The relaunch includes shows such as The Big Bang Theory, Young Sheldon and spin-off Georgie & Mandy's First Marriage, alongside new UK formats. The move is part of a broader simplification of WBD's UK portfolio and coincides with Sky Media taking over ad sales from January 2026.■

PARAMOUNT'S WBD BID FAILS TO SWAY KEY SHAREHOLDER

Paramount's revised $108.4 billion takeover offer for Warner Bros Discovery (WBD) has failed to fully convince Harris Oakmark, WBD's fifth-largest shareholder holding nearly a 4% stake. According to Reuters, the investor believes the updated bid, despite adjustments such as Larry Ellison personally guaranteeing over $40 billion of funding and a higher breakup fee, still falls short of being compelling.

Paramount's revised offer aimed to address concerns over financing and regulatory uncertainties, yet WBD's board has reiterated its preference for Netflix's competing proposal. While Netflix's cash bid values the company lower per share, the board points to greater certainty of financing, potential equity upside, and expected proceeds from a planned Discovery Global spin-off as key advantages.

Shareholders have until January 21, extended from the earlier January 8 deadline, to respond to Paramount's tender offer. Market

analysts say the competing bids underscore the strategic value of WBD's assets, which include HBO Max and iconic franchises such as Harry Potter, Lord of the Rings, and Superman. Some investors are expected to follow the board's recommendation, while others may still consider Paramount's revised proposal if Netflix does not improve its offer.

AKASHVANI & DOORDARSHAN EARN RS 588 CRORE

Akashvani and Doordarshan together generated Rs 587.78 crore from non-government advertisements between 2022 and 2025, the Lok Sabha was informed. The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) is simultaneously modernizing the broadcasters under the Rs 2,539.61 crore Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND) Scheme (2021–26).

आकाशवाणी

दूरदर्शन
सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

Improvements include upgrading studios and transmitters, expanding coverage, and enhancing digital presence through the OTT platform WAVES. Content reforms have been introduced to boost quality and regional diversity, with local artists engaged across 66 Programme Production Centres. Akashvani has launched audio-visual podcasts, while Doordarshan now integrates multiple channels on WAVES and apps like Online NewsONAIR, widening audience reach.

Structural reforms focus on revenue generation, multi-platform promotion, and content planning. Major national events such as Mahakumbh 2025, WAVES 2025, and ISRO satellite launches have been telecast live to ensure public outreach.

GOVERNMENT PROBES ALLEGED RS 100-CRORE TRP MANIPULATION IN KERALA

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has sought a report from Kerala Police regarding an alleged Rs 100-crore television rating manipulation case. Reports suggest a channel may have bribed a Broadcast Audience Research Council (BARC) employee to influence ratings.

B A R C
BROADCAST AUDIENCE RESEARCH COUNCIL INDIA

The ministry has requested details of action taken on the FIR reportedly filed in the matter. This investigation comes amid a review of the country's audience measurement framework, reflecting the government's focus on transparency, accountability, and regulatory compliance in television ratings. Officials say the inquiry will help ensure credibility in viewership metrics that underpin advertising and content decisions.■